

# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 09 NOVEMBER TO 15 NOVEMBER 2022

Inside News

बैंड-बाजा व बारात  
पर GST की नजर,  
साढे 5 लाख का बजट है  
तो 96 हजार लगेगा टैक्स

Page 3



सरकारी खर्च में  
कटौती की तैयारी! क्या  
भारत की चौखट पर आ  
चुकी है मंदी

Page 4



■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 09 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

डॉलर इंडेक्स का  
क्या है मतलब, इस  
पर क्यों नजर रखती  
है सारी दुनिया?



Page 5

editorial!

## सर्वर्णों को आरक्षण

गरीब सर्वर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है और इसके साथ ही आरक्षण के समग्र आधिकारिक स्वरूप में फिर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि, यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से किया है। तीन न्यायमूर्ति इस व्यवस्था के पक्ष में थे, जबकि प्रधान न्यायाधीश यू यू लिंग्ट और न्यायमूर्ति एस र्वांड्र ने इस आरक्षण के खिलाफ मत देते हुए इसे अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया है। पांच जजों की पीठ की ओर से बहुमत से आए इस फैसले के बाद सर्वर्ण गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलना जारी रहेगा। अभी तक संशय बना हुआ था कि गरीब सर्वर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था तो अनुसूचित जातियों-जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के लिए हुई थी। संसद ने 2019 में संविधान संशोधन के जरिये 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण देने के लिए कानून बनाया था। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब फैसला आया है और इसका व्यापक सामाजिक-राजनीतिक असर भी विभिन्न राज्यों में दिखेगा। जाहिर है, जब संसद ने कानून बना दिया है, तो उस कानून को चुनौती देना आसान नहीं है। फिर भी दो न्यायमूर्तियों की राय विपरीत रही है, यह वास्तव में संकेत है कि गरीब सर्वर्णों को आरक्षण देने का मामला आगामी दिनों में भी गरम रहेगा। क्या आरक्षण से असंतोष को दूर किया जा सकता है? क्या आरक्षण की बढ़ती मांग को खारिज किया जा सकता है? इसी फैसले में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा है, यह विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है? उन्होंने यह भी कहा कि गैर-बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। मतलब आरक्षण का सवाल बहुत व्यापक है और हमें इसके लाभ-हानि पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पिछड़ी जातियों, जनजातियों और गरीब सर्वर्णों के बीच भी जो वास्तविक वंचित हैं, उनको हम लाभ पहुंचा पाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अपने देश में अभी भी वंचितों की बड़ी संख्या है, जिसे मदद की जरूरत है। सरकारों को अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि किसी वर्ग को कागज पर आरक्षण देने से ज्यादा जरूरी है, उस वर्ग के जरूरतमंदों तक आरक्षण को पहुंचाना, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के इस अहम फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अधिकतर राजनीतिक पार्टीयों ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहां दिल्लित समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों के स्वर प्रतिकूल हैं। अखिर नाराजगी कहां है और क्यों है? दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय पहले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाने से इनकार कर चुका है। ओबीसी वर्ग को जब ज्यादा आरक्षण देने की बात आती है, तब इंदिरा साहनी मामले में लगी 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन जब 10 प्रतिशत आरक्षण गरीब सर्वर्णों को मिलेगा, तब आरक्षण की सीमा वैसे ही 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का अब कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह गया है। ऐसे में, आबादी के अनुपात में अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी को ज्यादा आरक्षण देने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पिछड़ी जाति या समाज में यह संदेश न जाए कि गरीब सर्वर्णों को तो आरक्षण मिलने लगा, पर हमें नहीं मिला।

## नई दिल्ली। एजेंसी

ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वोर्टेक्स के अंकड़ों के अनुसार, रूस पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस, जो 31 मार्च, 2022 तक भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेल का सिर्फ 0.2% प्रदानकर्ता था। अब रूस ने अक्टूबर में भारत को 935,556 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) कच्चे तेल की आपूर्ति की है, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% है, जो इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% से ज्यादा है।

रूसी तेल के लिए भारत की इच्छा तब से ज्यादा बढ़ गई जब उसने छूट पर व्यापार करना शुरू कर दिया क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मास्को को दंडित करने के लिए उससे तेल न लेने का फैसला लिया था। ऐसे में देश को अपना तेल बेचना था तो उससे स्कीम के तहत भारत को तेल देना शुरू किया। यह भारत के लिए भी सरल बन गया। ऊर्जा खुफिया फर्म वोर्टेक्स के अनुसार, भारत ने दिसंबर 2021 में रूस से सिर्फ 36,255 बीपीडी कच्चे तेल का आयात

किया, जबकि इराक से 1.05 मिलियन बीपीडी और सऊदी अरब से 952,625 बीपीडी का आयात किया गया था।

अगले दो महीनों में रूस से कोई आयात नहीं हुआ लेकिन फरवरी के अंत में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद मार्च में फिर से शुरू हो गया। भारत ने मार्च में 68,600 बीपीडी रूसी तेल का आयात किया, जबकि अगले महीने यह बढ़कर 266,617 बीपीडी

हो गया और जून में 942,694 बीपीडी पर पहुंच गया। लेकिन जून में, इराक 10.4 मिलियन बीपीडी तेल के साथ भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता था। उस महीने रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया।

## जहां मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे

अगले दो महीनों में आयात में मामूली गिरावट आई। वोर्टेक्स के अनुसार, अक्टूबर में बढ़कर

835,556 बीपीडी हो जाने से पहले वे सितंबर में 876,396 बीपीडी थे। इराक अक्टूबर में 888,079 बीपीडी आपूर्ति के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया, इसबां बाद सऊदी अरब 746,947 बीपीडी पर रहा। वहां, भारत सरकार रूस के साथ अपने व्यापार का जोरदार बचाव करती है। सरकार द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि उसे तेल वहां से लाना होगा जहां से वह सस्ता हो।

## रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में ज्ञुका अमेरिका, बोला- भारत को है हक

### वॉशिंगटन। एजेंसी

भारत कूटनीति के मामले में झांडे फहरा रहा है। ताजा मामला रूस से कच्चा तेल लेने का है। भारत ने साफ कहा है कि वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए जहां से मिलेगा, वहां से सप्तसाक तेल लेने का है। भारत ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी दौरों में भी कही थी। अब अमेरिका ने भी माना है कि भारत को जहां से चाहे

कच्चा तेल लेने का हक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ऊर्जा स्रोतों को उससे दूर रखा गया है। हालांकि, प्रवक्ता ने ये भी कहा कि रूस भरोसेमंद देश नहीं है। सुनिए, अमेरिकी प्रवक्ता ने क्या कहा। अमेरिकी प्रवक्ता ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के यूक्रेन मामले में रखे गए विचार

अलग-अलग नहीं हैं। प्रवक्ता ने सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में जो कहा था, वैसा ही रुख विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को जाकर दिया है। कुल मिलाकर भारत ने कहा है कि युद्ध आज के जमाने में किसी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से ही मसलों का हल निकल सकता है।

बता दें कि रूस की जंग में अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद

कर रहा है। यूरोप के देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। भारत ने लगातार वैश्विक मंचों पर कहा है कि यूक्रेन की समस्या का समाधान बातचीत से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में एससीओ की बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग बैठक की थी। तब मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत से निकालें। मोदी ने युद्ध की मुखालिफत की थी।

# News यू केन USE

गैस कारोबार में गिरावट  
से पेटोनेट का सितंबर  
तिमाही का शुद्ध लाभ  
चार प्रतिशत घटा

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की सिंतंबर तिमाही में शुद्ध लाभ चार प्रतिशत गिरकर 785.73 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को यह सूचना दी और कहा कि वैश्विक प्राकृतिक गैस कीमतों में तेजी से कारोबार में गिरावट आई जिससे उसका लाभ प्रभावित हुआ। कंपनी को एक साल पहले जुलाई-सिंतंबर तिमाही में 817.61 करोड़ रुपये एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था। पेट्रोनेट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अक्षय कुमार सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा दरों में तेजी आई थी, लेकिन पिछले 10-15 दिन से दरों में नरमी हो गई है। सिंह ने कहा कि कंपनी ने चालू तिमाही में अबतक का सबसे अधिक 15,986 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि पिछले साल यह 10,813 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने सात रुपये प्रति शेयर के विशेष अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है।

सौर ऊर्जा की मदद से भारत  
ने जनवरी से जून तक ईंधन  
लागत में चार अरब डॉलर की  
**बचत की: रिपोर्ट**  
नयी दिल्ली। एजेंसी

## नयी दिल्ली। एजेंस

भारत ने 2022 की पहली छमाही में सौर उत्पादन के जरिये ईंधन लागत में 4.2 अरब डॉलर और 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की। वृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इतने कोयले की बचत नहीं होने की स्थिति में पहले से दबाव में चल रही घेरू आपूर्ति पर भार और बढ़ जाता। ऊर्जा क्षेत्र के थिंक टैंक एम्बर, सेंटर फॉर रिसर्च ॲन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट में पिछले दशक में सौर ऊर्जा के विकास का विश्लेषण किया गया और पाया कि सौर क्षमता वाली शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में से पांच भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम एशिया में स्थित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सात प्रमुख एशियाई देशों - भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपीन और थाईलैंड में सौर उत्पादन के बूते जनवरी से जून 2022 तक लगभग 34 अरब डॉलर की संभावित जीवाश्म ईंधन लागत बची है। यह इसके अवधि के दौरान कुल जीवाश्म ईंधन लागत के नौ प्रतिशत के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया, "भारत में, सौर उत्पादन से वर्ष की पहली छमाही में ईंधन लागत में 4.2 अरब डॉलर की तथा 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत हुई।"

एयर इंडिया ने चीन डेवलपमेंट बैंक एविएशन से  
छह ए3 20 नियो विमान किराये पर लिए

सिंगापुरा एजेंसी

टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने चीन डेवलपमेंट बैंक फाइर्नेशियल लीजिंग कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुबंधी आयरलैंड की सीडीबी एविएशन से छह एयरबस ए320 नियो विमानों का एक बेड़ा पट्टेदार

(लीज) पर लिया है। बुधवार को सीढ़ीबी एशिया ने एक बयान में बताया कि विमानों को पट्टे पर लेने के समझौते पर हस्ताक्षर 'एयरलाइन इकोनॉमिक्स ग्रोथ फ्रॅटिवर्स एशिया पेसिफिक-2022' सम्मेलन से इतर किए गए। टाटा समूह ने एयरलाइन की खरीद के

बाद इसकी बहुस्तरीय परिवर्तन योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सीडीबी एविएशन वह पहली कंपनी है जो एयर इंडिया को अतिरिक्त ए 320 नियो विमानों को पट्टे पर देगी। एयर इंडिया को ये विमान 2023 की दूसरी छमाही में मिलेंगे। एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी

निपुण अग्रवाल ने समझौते के बारे में कहा, "यह एक महत्वपूर्ण समझौता है, जो हमें अत्याधिक विमानों के साथ अपने बेड़े को मजबूत करने में मदद करेगा।" बयान में कहा गया, "यह हमारी परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।"

युद्ध के बीच भारत ने कर दिया 'खेला'  
रूस से सस्ते में तेल खरीद  
अमेरिका को बेच रहा महंगा

नयी दिल्ली। एजेंस

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले नौ महीने से चल रहे युद्ध का असर दुनियाभर पर पड़ा है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हैं और कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि, इन प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बीच, भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल, भारत अमेरिका को वैक्यूम गैसआयल (न्डर) का एक्सपोर्ट कर रहा है। यह वीजीओ भारत ने रूस से सस्ती दरों पर खरीदा है और अमेरिका को महंगी दरों पर बेच रहा, जिससे मुनाफा भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि युद्ध के दौरान पश्चिमी देश रूस की आपूर्ति को बदलने के लिए विकल्प चाहते हैं। अमेरिका और कनाडा ने यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण पर रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूसी कच्चे और तेल उत्पादों के आयात पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध क्रमशः 5 दिसंबर और 5 फरवरी को प्रभावी होंगे।





डॉलर से 15 डॉलर प्रति बैरल के बीच है। स्ट्रोंने कहा कि इन दरों पर दिसंबर में भारत के वाडिनाम बंदरगाह से लोड होने वाले कार्गो के अमेरिका यांत्रियों जाने की संभावना है। इससे पहले, अफ्रामैक्स टॉकर शंघाई डॉन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वे जामनगर बंदरगाह से कम-से-कम 80,000 टन वीजीओ लोड किया, जो अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक में अमेरिका पहुंचा।

रूस से खरीद कर अमेरिका को  
बेच रहा भारत

इस बीच, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल  
आयातक भारत रूस से कच्चा तेल पहले के मुकाबले  
चाय बोर्ड ने अगले पांच से  
के लिए 1,000 करोड़ रुपये  
**सहायता मांगी**  
कोलकाता। एजेंसी

चाय बोर्ड ने वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले अगले पांच साल में चाय उद्योग के लिए 1,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। चाय बोर्ड के अध्यक्ष सौरव पहाड़ी ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को सौंपे गए बजट में छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) को मदद देने की ओर ध्यान दिया गया है, जो देश के कुल उत्पादन में 52 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पहाड़ी ने बृहस्पतिवार को यहां भारतीय चाय संघ (आईटीए) की वार्षिक आम बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “हमने वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि में लिए मंत्रालय को सौंपे गए बजट में 1,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।” उन्होंने कहा कि बजट मुख्य रूप से छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) की मदद देने के लिए है, जो देश के चाय उत्पादन में 52 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पहाड़ी ने कहा कि चाय बोर्ड ने पारंपरिक चाय उत्पादन के लिए भी समिक्षा मांगी थी, जिसका निर्यात बाजार अच्छा है।

स्वदेशी जागरण मंच ने  
ग्लाइकोफास्फेट पर प्रतिबंध लगाने के  
सरकार के फैसले का स्वागत किया

मयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने खर-पतवार नाशक ग्लाइकोफास्फेट के उपयोग को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए प्रभावात्मक सोमवार को कहा कि नागरिकों खासतौर पर किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी था। ज्ञात हो कि स्वदेशी जागरण मंच ग्लाइकोफास्फेट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहा है क्योंकि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अधिनी महाजन ने कहा कि खर-पतवार नाशक ग्लाइकोफास्फेट वे



# बैंड-बाजा व बारात पर GST की नजर, साढ़े 5 लाख का बजट है तो 96 हजार लगेगा टैक्स



रायपुर। एजेंसी

महंगी शादी पर टैक्स चोरी

किए जाने की आशंका को देखते हुए जीएसटी (उएक्स) का अमला

भी सक्रिय रहेगा। क्योंकि कोरोनाकाल के बाद इस वर्ष थोक में शादियां होंगी और लोग दिल खोलकर खर्च भी करेंगे। हालांकि उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो वेडिंग पैकेज के तहत शादी करेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बल्कि पैकेज के तहत एक बार में टैक्स देना होगा।

वैवाहिक सीजन के शुरू होते ही बैंड-बाजा और बारात पर जीएसटी विभाग पैनी नजर रखे हुए हैं। शादियों में होने वाले बैहिसाब खर्च पर टैक्स देना ही पड़ेगा। वर्ही इसकी चोरी करने पर विभाग सीधी कार्रवाई करते

हुए संबंधित वैवाहिक भवन से लेकर डेकोरेशन और बैंड बाजा वालों पर कार्रवाई करेगा। महंगी शादी पर टैक्स चोरी किए जाने की आशंका को देखते हुए जीएसटी (GST) का अमला भी सक्रिय रहेगा। क्योंकि कोरोनाकाल के बाद इस वर्ष थोक में शादियां होंगी और लोग दिल खोलकर खर्च भी करेंगे। हालांकि उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो वेडिंग पैकेज (Wedding Package) के तहत शादी करेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बल्कि पैकेज के तहत एक बार में टैक्स देना होगा।

## बुकिंग शुरू

वैवाहिक सीजन को देखते हुए भवनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। शादीवाले घरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत 12 से लेकर 18% तक का टैक्स है। मैरिज गार्डन, टैंट से लेकर बैंड बाजा और अन्य सभी में 12 से 18% का टैक्स (tax) देना पड़ेगा, जिससे लोगों का बजट बिगड़ेगा ही। हालांकि एक शादी में ओसतन 5.5 लाख का खर्च आता है। इस पर लोगों को 96000 रुपए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी। इसका सीधा असर शादी पर पड़ने के कारण बहुत सी सुविधाओं में कटौती करनी होगी। सबसे ज्यादा उस तबके पर पड़ेगा।

जो खुद ही होटल, टैंट, लाइट से लेकर बैंड बुक करते हैं।

टैक्स कलेक्शन के लिए विभागीय अमला जुड़ा हुआ है। इसकी चोरी करने वाले के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा।- अतुल गुप्ता, प्रधान आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी

सामान की खरीदी करने पर जीएसटी द्वारा निर्धारित टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें चोरी पकड़े जाने पर टैक्स चोरी की राशि के साथ ही उतनी ही रकम पेनाल्टी के रूप में देनी पड़ेगी।

- चेतन तारवानी, इनकम टैक्स बार एवं सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष और सीए

## ईंट निर्माताओं की सरकार से जीएसटी को घटाकर एक प्रतिशत करने की मांग

नयी दिल्ली। एजेंसी

करीब चार महीने से हड्डताल पर चल रहे ईंट निर्माताओं ने सरकार से ईंट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर छह प्रतिशत से घटाकर पहले के एक प्रतिशत के स्तर तक कम करने की मांग की है।

ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफूल्यूचरर्स पैकेज देश में न्युयूपैकेजर्स के महासचिव

ओमवीर सिंह भाटी ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पीटीआई-भाषा को बताया कि नयी जीएसटी दर एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी है। इससे पहले कंपोजिशन स्कीम के तहत ईंट निर्माताओं पर एक प्रतिशत जीएसटी लगता था।

उन्होंने कहा, “हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं। पूरे देश में हमारे भट्टे इस समय बंद हैं

क्योंकि मांग के अभाव और उच्च



लागत के कारण हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। हम

सरकार से जीएसटी को कम करने

की मांग करते हैं।” उन्होंने ईंट बनाने वाली इकाइयों के बंद होने के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले तीन से चार महीनों से भट्टा मालिक देशव्यापी हड्डताल पर हैं। डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले व्यवसायों पर एक प्रतिशत जीएसटी था। एआईबीटीएमएफ

के अधिकांश सदस्यों का कारोबार इसी सीमा में है। भाटी ने इस मुद्दे के बारे में कहा कि हालांकि, सरकार ने केवल ईंट उद्योग के लिए जीएसटी को बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया है और यह दूसरी अन्य चीजों के लिए पहले की ही तरह है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दर में वृद्धि का निर्णय पिछले साल जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया था। उन्होंने कहा कि ईंटों के

लिए कच्चे माल में से एक कोयले पर भी जीएसटी दर को पहले के पांच प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। यह एक श्रम प्रधान उद्योग है और सरकार को जीएसटी बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत में लगभग 1.5 लाख से अधिक ईंट भट्टे हैं। भाटी ने कहा कि बंद के कारण कीरी तीन करोड़ कर्मचारी काम से दूर हैं।

## जीएसटी में सिर्फ एक दर चाहते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन देबराय

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन विवेक देबराय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के सुझाव नहीं माना जाए। देबराय ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र और राज्यों का कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 15 प्रतिशत है, जबकि सार्वजनिक ढांचे पर सरकार के खर्च की मांग कहीं ऊंची है। उन्होंने कहा,

“जीएसटी पर यह मेरी राय है। कर की सिर्फ एक दर होनी चाहिए। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कभी मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि यदि ‘अभिजात्य प्रकृति’ और अधिक उपभोग वाले

उत्पादों पर अलग-अलग कर दरें हटा दी जाएं, तो इससे मुकदमेबाजी कम होगी। देबराय ने कहा, “हमें यह समझने की जरूरत है कि उत्पाद

11.5 प्रतिशत है। ईएसी-पीएम

के चेयरमैन ने कहा,

“या तो हम कर देने के लिए तैयार रहें या सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की कम आपूर्ति के लिए। सरकार द्वारा जो कर मुक्तता या रियायत दी जाती है वह जीडीपी के 5-5.5 प्रतिशत बेराबर है।”

उन्होंने कहा कि कर चोरी गैरकानूनी है, लेकिन मुक्तता या छूट के प्रावधान के जरिये कर से बचाव कानूनी रूप से सही है। देबराय ने सवाल किया कि क्या हमें इस तरह छूट की जरूरत है। जितना हम कर-मुक्तता देंगे वह उतना जटिल बनेगा। “हमारा ऐसा सुगम कर ढांचा क्यों नहीं हो सकता, जिसमें किसी तरह का ऐसा प्रावधान नहीं हो।” देबराय ने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर के बीच ‘कृत्रिम अंतर’ को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे प्रशासनिक अनुपालन का बोझ कम होगा।

कोई भी हो, जीएसटी दर एक होनी चाहिए। यदि हम प्रगतिशीलता दिखाना चाहते हैं तो यह प्रत्यक्ष करों के जरिये होनी चाहिए, जीएसटी या अप्रत्यक्ष करों के जरिये नहीं।” उन्होंने कहा कि उनके इस विचार को ईएसी-पीएम का सुझाव नहीं

किया जाना चाहिए।

देबराय ने कहा कि जीएसटी



## विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

# 83052-99999

[indianplasttimes@gmail.com](mailto:indianplasttimes@gmail.com)



## News दू केन USE

## सरकार चीन के 'मेटल कटर व्हील' पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाएगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने चीन से आयात किए जाने वाले 'मेटल कटर व्हील' पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा लेवी लगाने की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने चीन से आयात किए जाने वाले इस उत्पाद की कथित डंपिंग की जांच की थी। महानिदेशालय ने सिंतंबर में शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। 'मेटल कटर व्हील' का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में लोहा और अन्य सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, "केंद्र सरकार ने नामित प्राधिकरण (डीजीटीआर) के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।" डीजीटीआर की सिफारिशों पर राजस्व विभाग अंतिम निर्णय करता है।

## सीमेंस ने रेल डिब्बों के उत्पादन के लिए औरंगाबाद में कारखाना लगाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सीमेंस लिमिटेड ने रेल डिब्बों के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है। कंपनी ने बुधवार को जारी बयान में कहा, "सीमेंस ने भारत और दुनियाभर में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए औरंगाबाद में एक अत्याधुनिक कारखाना स्थापित किया है। यह कारखाना निर्यात ॲडर पर 200 से अधिक रेल बोगियों की आपूर्ति करेगा।" बयान के अनुसार, रेल बोगियां सीमेंस के वैश्विक डिजाइन 'एसएफ 30 कॉम्बिनो प्लस' पर आधारित होंगी। यह इस श्रेणी में सर्वोत्तम यात्री अनुभव और आसान रखरखाव प्रदान करती है।

## राजमार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करें राज्य: सड़क मंत्रालय

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह यातायात प्रबंधन और परिचालन के लिए तथा भावी परियोजनाओं के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत अधिक अवैध कब्जे हैं। इसमें मंत्रालय ने कहा, "यह जानकारी मिली है कि ढाबेवालों, सज्जी विक्रेताओं आदि ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण कर रखे हैं।" पत्र में आगे कहा गया, "मंत्रालय का ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी एवं अस्थायी अवैध कब्जे यातायात प्रबंधन और परिचालन तथा भावी परियोजनाओं के लिए चिंता का गंभीर विषय है।"

## सरकारी खर्च में कटौती की तैयारी! क्या भारत की चौखट पर आ चुकी है मंदी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को तय लक्ष्य के भीतर रखने के लिए सरकारी खर्च में तीन साल में पहली बार कटौती कर सकती है। यह कटौती चालू वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में की जा सकती है। खर्च में कटौती इस तरह से की जाएगी, जिससे जीडीपी ग्रोथ पर इसका असर कम से कम पड़े। सरकार पहले ही कह चुकी है कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के परिपेक्ष्य में 6.4 प्रतिशत रखने के लिए वह हरसंभव प्रयास करेगी। सरकार वित्तीय घाटे पर लगाने के उपाय कर रही है, जो फिलहाल 4 से 5 फीसदी के एतिहासिक स्तर से ऊपर है। गौरतलब है कि 2020-21 में कोरोना महामारी के पहले साल के दौरान वित्तीय घाटा 9.3 फीसदी तक बढ़ गया था।

सूत्रों के अनुसार इस बारे में महामंथन चल रहा है। किस-किस सेक्टर में सरकारी खर्च में कटौती की जाए, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। सरकारी आमदनी और खर्च के भीतर के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

एक अप्रैल से शुरू हुए 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी खर्च 39.45 लाख करोड़ के बजट से काफी कम 70 से 80 करोड़ रुपये तक हो सकता है। राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य के भीतर रहें, इसके लिए कदम भी उठाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि

कारण है कि सरकार चालू खाते के मोर्चे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। क्यों कर रही है सरकार ऐसा

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत से निपटने के लिए कदम उठा रही है। देश अपनी

और अन्य देशों में महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार और आरबीआई मिलकर प्रयासरत हैं।

इधर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। भारत का वित्तीय घाटा तय लक्ष्य से ज्यादा होगा। फिच के अनुसार भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी के परिपेक्ष्य में 6.4 फीसदी तथा साल 2025-25 तक इसे जीडीपी के परिपेक्ष्य में 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य किया हुआ है। फिच का कहना है कि भारत की इकॉनमी के जो हालात हैं, उसे देखते हुए भारत को सब्सिडी और अन्य मदों में ज्यादा खर्च करना होगा। ऐसे में उसका खर्च बढ़ता जाएगा। ऐसे में भारत को अपनी आमदनी भी बढ़ानी होगी। जिस तरह के वैश्विक इकॉनमी में अनिश्चितता की स्थिति है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि भारत खर्च और आमदनी के बीच ज्यादा संतुलन बना सकने में कामयाब होगा।



चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय तय लक्ष्य में रहे ताकि अगले वित्त वर्ष में इस मोर्चे पर ज्यादा चुनौतियां न रहें। आईएमएफ ने साफ तौर पर कहा है कि अगले वित्त वर्ष में ग्लोबल मंदी आ सकती है। उससे हालात बिगड़ सकती है। यही

कच्चा तेल की जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात के जरिये पूरा करता है। डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में कमी से आयात महंगा हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल समेत जिससे के दाम उच्च स्तर पर हैं। इससे भारत



## रेलवे ने 82 प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक 1,223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है। एक साल पहले इसी अवधि में 895 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण के मुकाबले यह 36.64 प्रतिशत अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार, कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर बॉड गेज नेटवर्क के अंतर्गत हैं। इसमें से 53,470 किलोमीटर यानी 82.08 प्रतिशत रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मंत्री ने कहा, "भारतीय रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप न केवल बेहतर तरीके से ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि दक्षता बढ़ने के साथ ईंधन खर्च में कमी आएगी और फलतः कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी।" इससे पहले, 2020-21 में सबसे अधिक 6,015 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर बॉड गेज नेटवर्क (कोंकण रेलवे समेत) के अंतर्गत हैं। इसमें से 53,470 किलोमीटर यानी 82.08 प्रतिशत रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

## मोटे अनाज का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार विदेश में भारतीय दूतावासों से मदद लेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है जिसमें विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ-साथ वैश्विक खुदरा सुपरमार्केट कैरफोर एवं वॉलमार्ट को साथ लेने की बात शामिल है। रणनीति के हिस्से के रूप में, विदेशों में भारतीय दूतावासों को घेरू मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए, शामिल किया जाएगा। दूतावासों को संभावित खरीदारों की पहचान करने के लिए भी कहा जाएगा जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट। उन्हें बिजनेस-टू-बिजनेस (बी 2 बी) बैठकें आयोजित करने एवं भारतीय मोटे अनाज के लिए साझेदारी कायम करने के लिए कहा जायेगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रचार रणनीति के तहत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खुदरा सुपरमार्केट जैसे लुलु समूह, कैरफोर, अल जीरा, अल माया, वॉलमार्ट को भी मोटे अनाज की ब्रांडिंग और प्रचार के मक्सद से



भर में लोकप्रिय बनाना है। भारत के शीर्ष पांच बाजार उत्पादक राज्य - राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। बाजारों के निर्यात का हिस्सा कुल मोटे अनाज उत्पादन का एक प्रतिशत है। भारत से मोटे अनाज के निर्यात अधिक का हो जाएगा। मोटा अनाज कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। दुनिया में प्रमुख मोटे अनाज आयात करने वाले देश इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मेक्सिको, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और नीदरलैंड हैं।

# डॉलर इंडेक्स का क्या है मतलब, इस पर क्यों नजर रखती है सारी दुनिया?



रुपये में मजबूती की खबर हो या गिरावट की, ब्रिटिश पौंड अचानक कमज़ोर पड़ने लगे या रूस और चीन की करेंसी में उथल-पुथल मची हो, करेंसी मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों में डॉलर इंडेक्स का जिक्र जरूर होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की हलचल से जुड़ी खबरों में तो रेफरेंस के लिए डॉलर इंडेक्स का नाम हमेशा ही होता है। ऐसे में मन में यह

सवाल उठना लाज़मी है कि करेंसी मार्केट से जुड़ी खबरों में इस इंडेक्स को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डॉलर इंडेक्स आखिर है क्या?

**डॉलर इंडेक्स क्या है?**  
डॉलर इंडेक्स दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमज़ोरी का संकेत देने वाला इंडेक्स है।

इस इंडेक्स में उन देशों की मुद्राओं को शामिल किया गया है, जो अमेरिका के सबसे प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इस इंडेक्स शामिल 6 मुद्राएँ हैं – यूरो, जापानी येन, कनाडाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक। इन सभी करेंसी को उनकी अहमियत के हिसाब से अलग-अलग वेटेज दिया गया है। डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाता है, डॉलर को उतना मजबूत माना जाता है, जबकि इसमें गिरावट का मतलब ये है कि अमेरिकी करेंसी दूसरों के मुकाबले कमज़ोर पड़ रही है।

## डॉलर इंडेक्स का इतिहास

डॉलर इंडेक्स की शुरुआत अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने 1973 में की थी और तब इसका बेस 100 था। तब से अब तक इस इंडेक्स में सिर्फ एक बार बदलाव हुआ है, जब जर्मन मार्क, फ्रैंच फ्रैंक, इटालियन लीरा, डच गिल्डर और बेल्जियन फ्रैंक को हटाकर इन सबकी की जगह यूरो को शामिल किया

गया था। अपने इतने वर्षों के इतिहास में डॉलर इंडेक्स आमतौर पर ज्यादातर समय 90 से 110 के बीच रहा है, लेकिन 1984 में यह बढ़कर 165 तक चला गया था, जो डॉलर इंडेक्स का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं इसका सबसे निचला स्तर 70 है, जो 2007 में देखने को मिला था।

## डॉलर इंडेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

डॉलर इंडेक्स में भले ही सिर्फ 6 करेंसी शामिल हों, लेकिन इस पर दुनिया के सभी देशों में नज़र रखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है। न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, बल्कि तमाम देशों की सरकारों के विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर सबसे प्रमुख करेंसी है। यूएस फेड के आंकड़ों के मुताबिक 1999 से 2019 के दौरान अमेरिकी महाद्वीप का 96 फीसदी ट्रेड डॉलर में हुआ,

## डॉलर इंडेक्स में किस करेंसी का कितना वेटेज?

डॉलर इंडेक्स पर हर करेंसी के एक्सचेंज रेट का असर अलग-अलग अनुपात में पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज यूरो का है और सबसे कम स्विस फ्रैंक का।

यूरो : 57.6%

जापानी येन : 13.6%

कैनेडियन डॉलर : 9.1%

ब्रिटिश पाउंड : 11.9%

स्वीडिश क्रोना : 4.2%

स्विस फ्रैंक : 3.6%

हर करेंसी के अलग-अलग वेटेज का मतलब ये है कि इंडेक्स में जिस करेंसी का वज़न जितना अधिक होगा, उसमें बदलाव का इंडेक्स पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। जाहिर है कि यूरो में उतार-चढ़ाव आने पर डॉलर इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

जबकि एशिया-पैसिफिक रीजन

में यह शेयर 74 फीसदी और बाकी दुनिया में 79 फीसदी रहा। सिर्फ यूरोप ही ऐसा ज़ोन है, जहां सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूरो में होता है। यूएस फेड की वेबसाइट के मुताबिक 2021 में दुनिया के तमाम देशों में घोषित विदेशी मुद्रा भंडार का

## इस्मा ने चीनी नियंत्रित नीति की सराहना की, अतिरिक्त नियंत्रित को मंजूरी मिलने का भरोसा जताया

### नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने सोमवार को 31 मई तक 60 लाख टन चीनी नियंत्रित की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। साथ ही वर्ष 2022-23 सत्र में 30 लाख टन अतिरिक्त चीनी नियंत्रित को मंजूरी दिये जाने का भरोसा जताया। चीनी उद्योग ने सरकार से 90 लाख टन चीनी के नियंत्रित की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन खाद्य मंत्रालय ने पांच नवंबर को चीनी सत्र 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के 31 मई तक कोटा के आधार पर केवल 60 लाख टन चीनी नियंत्रित की अनुमति दी थी। सरकार ने कहा है कि वह घरेलू उत्पादन का आकलन करने के बाद आगे की मात्रा पर विचार कर सकती है।

इस्मा ने एक बयान में कहा, “चीनी उद्योग को भरोसा है कि सरकार 30 लाख टन अतिरिक्त चीनी नियंत्रित करने की अनुमति

## क्या बाजार में नहीं मिल रहा है अमूल का मक्खन? जानिए क्या है सच्चाई

### नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

“सुबह के समय ज्यादातर लोग ब्रेड में मख्खन कीमतों में स्थिरता आयेगी, किसानों को समय पर गत्ता मूल्य का भुगतान किया जा सकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि चीनी मिलों पर कोई अतिरिक्त लागत बोझ न आये। इस्मा ने सरकार की चीनी नियंत्रित नीति की सराहना की और कहा कि व्यापार योग्य कोटा योजना चीनी नियंत्रित में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और त्योहारों के दौरान खुदरा कीमतों में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने एक जून से चीनी सत्र 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के अंत तक चीनी नियंत्रित को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे 2021-23 सत्र के दौरान लगभग 1.1 करोड़ टन चीनी का नियंत्रित किया गया और देश के लिए 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

### सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे वजह

अमूल मख्खन नहीं मिलने से परेशान लोग अब सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुंबई,



### जानिए क्या कह रहे लोग

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाली रेनू जोशी के मुताबिक,

अमूल का मक्खन बाजार में कम मिल रहा है। अमूल के मक्खन के छोटे पैक बाजार में मिल रहे हैं। बड़े पैक मिलने में समस्या आ रही है। वहीं कई लोगों का कहना है कि उनके एरिया में जब मक्खन नहीं मिलता तो उन्होंने जैम खरीदा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमूल के मक्खन के छोटे वाले पैकट दुकानों पर उपलब्ध हैं लेकिन बड़े वाले नहीं मिल पाए हैं।



# एसुस ने भारत में दुनिया का पहला 17.3 इंच का फोल्डेबल लैपटॉप- ज़ेनबुक 17 फोल्ड ओएलईडी लैपटॉप अभूतपूर्व नवाचार का बेमिसाल उदाहरण पेश करता है। अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट और हल्का 12.5' फोल्डेबल ओएलईडी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ताइवान की टेक्नोलॉजी जायंट, एसुस इंडिया ने भारत में दुनिया का पहला 17.3 इंच का फोल्डेबल ओएलईडी लैपटॉप लॉन्च करने की घोषणा की है। यह ज़ेनबुक 17 फोल्ड ओएलईडी लैपटॉप अभूतपूर्व नवाचार का बेमिसाल उदाहरण पेश करता है। अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट और हल्का 12.5' फोल्डेबल ओएलईडी

लैपटॉप 6 मोड्स के साथ एक बहुमुखी 17.3 इंच डिवाइस के रूप में इजात हुआ है, जबकि इसका वजन केवल 1.5 किलोग्राम (बिना कीबोर्ड के) ही है। ज़ेनबुक 17 फोल्ड ओएलईडी नवीनतम 12वीं जनरेशन के इंटेल रु कोर TM i7-1250U प्रोसेसर से लैस है, जिसे 10 कोर (दो परफॉर्मेंस कोर और आठ एफिशिएंसी कोर) के साथ

डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए सभी कार्यों को आसानी से हैंडल करने की अधिकतम फ्रीक्वेंसी 4.7 है। इसके अलावा, लैपटॉप 16GB 5200MHz LPDDR5 रैम और 1TB PCIe 4.0 x4 6500 MB/s SSD के साथ आता है। ज़ेनबुक 17-फोल्ड विद ओएलईडी के लॉन्च की घोषणा यूजर्स के लिए 329,990 रुपए में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रिप्पणी करते हुए। इन्टेल और बीओई के साथ विकसित किया गया यह लैपटॉप एक बेशकीमती और क्रॉटिकारी अनुभव प्रदान करता है, जो लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी के साथ डेस्कटॉप की उत्पादकता को बढ़ाव देता है। यह

दुनिया का पहला 17.3 इंच का फोल्डेबल लैपटॉप है, जो प्रोप्राइटरी फोल्डेबल हिंज डिज़ाइन का उपयोग करता है।

इंटेल और बीओई के साथ विकसित किया गया यह लैपटॉप एक बेशकीमती और क्रॉटिकारी अनुभव प्रदान करता है, जो लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी के साथ डेस्कटॉप की उत्पादकता को बढ़ाव देता है। यह

## संतूर ने ब्रांड रिलॉन्च की घोषणा की, साबुन को ज्यादा नमी, खुशबू, और नई पैकेजिंग के साथ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाईटिंग के फ्लैगशिप ब्रांड, संतूर ने अपने कलासिक हल्दी एवं चंदन सोप, संतूर ऑरेंज के रिलॉन्च की घोषणा की है। यह रिलॉन्च युवा उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए नए व ताजा रुख, “थिंक यंग” के साथ किया गया है। इस प्रोडक्ट अपग्रेड में नई पैकेजिंग, बेहतर खुशबू और ज्यादा नमी के गुणों का शामिल किया गया है।

चंदन और हल्दी के गुणों एवं खुशबू के साथ संतूर ज्यादा युवा स्किन का वादा करता है। प्राकृतिक नमी के गुणों के साथ यह उत्पाद नहाने का ऐश्वर्यपूर्ण अनुभव देते हुए ज्यादा निखरी व नम त्वचा प्रदान करता है। साहसिक परिवर्तन का संकेत देते हुए थिंक यंग अभियान

महिला की पहचान के बारे में आम रुद्धियों और लंबे समय से चली आ रही धरणाओं को तोड़ता है। आज की संतूर महिला जीवन के प्रति युवा और नए रुख के साथ हर सीमा से परे है। यह महिलाओं को यह कहने के लिए प्रोत्साहित करता है - “हाँ, क्यों नहीं?”। उसका बच्चा भी इस आकर्षक सफर का हिस्सा है, जो अपनी माँ का सहयोग करता है, और उसे उपलब्धियाँ हासिल करते हुए एवं उत्साह के साथ यह कहते हुए देखता है... “क्यों नहीं?”।

रिलॉन्च के अवसर पर श्री नीरज खत्री, चीफ एग्ज़िक्यूटिव, कंज्यूमर केयर, इंडिया एवं सार्क बिज़नेस, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाईटिंग ने कहा, “संतूर विप्रो कंज्यूमर केयर का फ्लैगशिप ब्रांड में से एक बना देगी।”

है। तीन दशकों से ज्यादा समय से लाखों भारतीय महिलाएं संतूर पर भरोसा करती आई हैं। आज संतूर चंदन और हल्दी सोप युवा दिखने वाली स्किन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी विकास योजना के तहत संतूर निरंतर इनोवेट करते हुए नए युग के उपभोक्ताओं की लगातार बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाता है। हमारे फ्लैगशिप और उपभोक्ताओं की लगातार बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाता है। हमारे इंडेक्स के घटकों में निवेश करने वाला ओपन-एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है; इसमें अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर जोखिम और अपेक्षाकृत कम क्रोडिट जोखिम है। नया फंड निपटी एसडीएल सेप्टेंबर 2026 इंडेक्स को ट्रैक करेगा। स्कीम का निवेश उद्देश्य प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न के अनुरूप निवेश रिटर्न प्रदान करना है, जैसा कि निपटी एसडीएल सितंबर 2026 इंडेक्स द्वारा व्याय से पहले दर्शाया गया है, जो ट्रैकिंग त्रुटियों के अधीन है। हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है

## कैच के नए कैम्पेन, ‘क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता’ में नजर आयेंगे

### अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डीएस समूह के अंग, डीएस स्पाइसको द्वारा कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस के लिये लॉन्च किए गए एक नए कैम्पेन में बॉलीवुड के कलाकार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर नजर आयेंगे। इस नए कैम्पेन में कैच की नई पोजीशनिंग ‘क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता’ पर जोर दिया गया है। इस कैम्पेन की परिकल्पना डेंटसू क्रिएटिव ने की है और इसमें दिखाया गया है कि खाना कई सारी चीजों से मिलकर बनता है- उनमें यादें होती हैं, रिश्ते होते हैं, परंपराएं और मूल्य होते हैं। इस तरह यह कैम्पेन ब्रांड को उपभोक्ता

मेरे जीवन में प्रधान रही है। इस भावना को पढ़े पर निभाना मेरे लिए खुशी की बात है।’ इस मौके पर भूमि पेडनेकर ने कहा, ‘कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस अपने उत्पादों की बड़ी श्रृंखला के साथ एक घरेलू नाम बन चुका है। मेरा मानना है कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता, खाने से होकर जाता है। और इसलिए यह बात ‘क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता’ की सोच को और भी मजबूत करती है।’ इस कैम्पेन के बारे में श्री संदीप घोष, बिज़नेस हेड, डीएस स्पाइसको प्राइवेट लिमिटेड का कहना है, ‘मसाले भारतीय भोजन की जान हैं। एक

ब्रांड के तौर पर हम मसालों की अपनी रेंज के साथ ग्राहकों के किचन पर राज करना चाहते हैं। यह नया कैम्पेन खाने के साथ होने वाली ग्राहकों की बातचीत की अलग-अलग बारीकियों को सामने लेकर आएगा। इस कैम्पेन के पीछे की सोच के बारे में, अजय गहलोत, ग्रुप चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, डेंटसू क्रिएटिव ने कहा, ‘हमारे लिये खाना शरीर को ताकत देने से कहीं बढ़कर होता है, खाने की मदद से हमें खुद को अभिव्यक्त करने और यह दिखाने में मदद मिलती है कि हम एक-दूसरे की कितनी परवाह करते हैं।

प्रतियोगिता नॉकआउट कम लीग के आधार पर खेली जा रही है। इस स्पर्धा के आधार पर प्रथम चार टीमें पानीपत में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय स्पर्धा के लिए क्वालीफाई करेंगे। 10

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में सबसे तेजी से बढ़ते फंड हाउसों में एक, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड ऑफर-एक्सिस निपटी एसडीएल सेप्टेंबर 2026 डेट इंडेक्स फंड को लॉन्च किया। यह निपटी एसडीएल सेप्टेंबर 2026 इंडेक्स के घटकों में निवेश करने वाला ओपन-एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है; इसमें अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर जोखिम और अपेक्षाकृत कम क्रोडिट जोखिम है।

एक निपटी फंड के रूप में, इस उत्पाद का उद्देश्य प्रतिष्ठित इंडेक्स प्रदाताओं द्वारा बनाए गए निर्दिष्ट इंडेक्स को दोहराना है। लक्ष्य परिपक्वता रणनीतियों की ‘परिपक्वता तक धारित’ प्रकृति का उद्देश्य उन निवेशकों के लिए अवधि जोखिम को कम करना है जो पूरी फंड अवधि के दौरान निवेश किए रखते हैं।

कि योजना के निवेश उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा। आदित्य पगरिया इसके फंड प्रबंधक हैं। इसकी न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रु. और उसके बाद 1/- रुपये के गुणकों में है।

टारगेट मैच्योरिटी फंड निवेशकों को विशिष्ट मैच्योरिटी बेकेट तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। इस तरह की रणनीति की पारदर्शी प्रकृति निवेशकों को पोर्टफोलियो और इंस्ट्रुमेंट मिक्स की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है। एक निष्क्रिय फंड के रूप में, इस उत्पाद का उद्देश्य प्रतिष्ठित इंडेक्स प्रदाताओं द्वारा बनाए गए निर्दिष्ट इंडेक्स को दोहराना है। लक्ष्य परिपक्वता रणनीतियों की ‘परिपक्वता तक धारित’ प्रकृति का उद्देश्य उन निवेशकों के लिए अवधि जोखिम को कम करना है जो पूरी फंड अवधि के दौरान निवेश किए रखते हैं।

## पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल स्पर्धा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

नवम्बर को खेले गए क्वालीफाइंग राउंड के मुकाबलों में रानी दुगावीती विश्वविद्यालय जबलपुर ने मुंबई विश्वविद्यालय को कड़े मुकाबलों में 56-48 स्वर्णम गुजरात ने गत वर्ष की विजेता राजस्थान विश्वविद्यालय को 67-53, आईटीएम ग्वालियर ने सावित्रीबाई फुले पुणे को 75-53, से तथा एलएमएनआईपी ग्वालियर ने आरटीएमएनयू नागपुर को 57-40 अंकों से पराजित कर अंतिम चार में अपना स्थान बनाया। आयोजन अध्यक्ष सुप्रिया ठाकुर और मनीष जायसवाल ने बताया कि समापन समारोह में एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जगदाले मुख्य अतिथी होंगे।



# ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के 'मित्रता राजदूत' बने

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, नीरज चोपड़ा को 'मित्रता राजदूत' नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में, भारत के खेलों के प्रतिभाशाली सुपरस्टार भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के रोमांचक, शानदार और आश्चर्यजनक स्थानों का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। नीरज चोपड़ा ने अक्सर टूर्नामेंट्स खेलने और प्रशिक्षण लेने के लिए



इस वर्ष सितंबर में ज्यूरिख में डायमंड लीग चैंपियनशिप जीतने के बाद, नीरज और

छुट्टियों की मस्तियों का एक अंश था, वे जिनेवा शहर भी गए, जिसे उन्होंने दौड़ते हुए

और एक ई-टुकटुक की सवारी के जरिए देखा जो उन्हें संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ गाँधी प्रतिमा तक राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लेकर गया। लेकिन नीरज चोपड़ा होने के नाते, उन्हें जिनेवा के प्रसिद्ध लैंडमार्क - 'जेट डी'ओ को देखने के लिए जानी-मानी झील जिनेवा तक रिवर राफिटंग करके अपनी यात्रा को पूरा किए बारे न

उनके करीबी दोस्त, जो स्विट्जरलैंड में उनसे मिले थे, छुट्टी मानाने के लिए गए, जो उनकी रोमांचक प्रवृत्ति के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। उनके कार्यक्रम में सब कुछ शामिल था - इंटरलेकन में कैन्यन जंपिंग, स्काई डाइविंग, जेटबोट के साथ-साथ जंगलाजोक पर स्नो स्कूटर और स्लेज से लेकर ज़र्मेंट में मॉन्स्टर बाइकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और हेलीकॉप्टर की यात्रा। लेकिन रोमांच उनके

रह सके। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के 'मित्रता राजदूत' के रूप में, नीरज चोपड़ा इस देश के अपने अनुभवों के बारे में बतायेंगे ताकि उसे घूमने-फिरने के लिए एक आदर्श ठिकाने और हाइकिंग, बाइकिंग, हल्के-फुल्के और ज़बरदस्त रोमांच और निश्चित रूप से स्नो स्पोर्ट्स के लिए, नए या अनुभवी पेशेवरों सभी के लिए सबसे अच्छे स्थान के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।

## इंडियन प्लास्ट टाइम्स

### सयाजी इंदौर ने केक मिक्सिंग समारोह 2022 जश्न का माहौल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सयाजी होटल इंदौर ने हाल ही में त्योहारी सीजन की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण एवं अनुष्ठान के केक मिक्सिंग समारोह का आयोजन किया। मस्ती भरे इस उत्सव में शहर के संग्रांत अतिथि, ब्लॉगर और इन्फ्लूएंसर शामिल हुए, जिनके साथ होटल के कर्मचारी भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर समारोह को हर्ष एवं खुशियों से भर दिया। कार्यक्रम में बादाम, पिस्ता, काजू सहित सूखे मेवे और ताजे पिसे हुए सुगंधित मसालों की विभिन्न प्रकार की ड्रिंक्स के साथ मिक्सिंग की गई थी। इस भीगे हुए मिश्रण को, स्वादिष्ट केक बनाने के उद्देश्य से, कुछ सप्ताह के लिए अलग रख दिया जाता है। हाई-टी की मेजबानी का आनंद लेते हुए, मेहमानों ने शानदार माहौल में अपनी शाम बिताई और सयाजी टीम के साथ शुभकामनाएं साझा की और साथ मिलकर शहर में उत्सव का स्वागत किया।

इस अवसर पर श्री रक्षित शर्मा, जीपीएम - वाइस प्रेसिडेंट - ऑपरेशंस, पीपुल, सेल्स एवं रेवन्यू - सयाजी होटल लिमिटेड ने बताया कि 'केक मिक्सिंग दुनिया भर में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न का मूड बना रही है जो बहुत पुरानी परंपरा है। शहर में पांच सितारा होटल संचालन में अग्रणी होने के कारण, हम शहर में उत्सवों की शुरुआत करने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम उन सभी मेहमानों के शुक्रगुजार हैं जो केक मिक्सिंग में हमारे साथ शामिल हुए और हम अपने होटल में ऐसे कई अन्य समारोहों का आयोजन करके शहर की उत्सवधर्मिता में अपना योगदान देते रहने के लिए तैयार हैं।'

# फोनपे ने लॉन्च के 3 महीने में ही लगाए 10 लाख से ज्यादा स्मार्टस्पीकर

स्मार्टस्पीकर के ज़रिए 100 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन भारत में मर्चेंट पेमेंट की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फोनपे भारत का अग्रणी पिनन्टेवन प्लाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म है। वर्ष पानी ने हाल ही में स्मार्टस्पीकर लॉन्च किए हैं।

भारत में 10 लाख कारोबार मालिक मर्चेंट पार्टनर्स अब इन स्मार्टस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही, कंपनी ने लॉन्च के सिर्फ 3 महीने में 1 करोड़ 1 बिलियन ट्रांजैक्शन इस डिवाइस के ज़रिए किए हैं। इससे कंपनी ने देश भर में अपने आँफ्लाइन मर्चेंट पेमेंट सुविधा को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इस साल अगस्त में मर्चेंट लोकेशन पर सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट ट्रैकिंग के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस साल अगस्त में मर्चेंट लोकेशन पर सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट ट्रैकिंग के लिए इसकी शुरुआत की गई थी।

फोनपे ने हमेशा अपने कारोबार मालिकों के लिए पेमेंट सुविधा को आसान बनाने की कोशिश की है। हम अपने सहयोगियों को कारोबार चलाने और उसे बढ़ाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने इंटरऑपरेबल कोड की शुरुआत की थी। इससे कारोबार मालिकों के लिए किसी भी यूपीआई लङ्ग एप्लिकेशन से डिजिटल पेमेंट पेमेंट ट्रैक करना कारोबार मालिकों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फोनपे के स्मार्टस्पीकर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्मार्टस्पीकर सभी पेमेंट ट्रैक करते हैं, जिससे समय की भी बचत होती है।

\* कोड पर पेमेंट ट्रैक करना कारोबार मालिकों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फोनपे के स्मार्टस्पीकर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्मार्टस्पीकर सभी पेमेंट ट्रैक करते हैं, जिससे समय की भी बचत होती है।

स्मार्टस्पीकर में कई बेहतरीन सुविधाएं हैं, जैसे कि पेमेंट अलर्ट इसके साथ ही यह सुरक्षित और विश्वसनीय है। इसकी मदद से कारोबार मालिकों को अब उनकी गैर-मौजूदगी में गलत ट्रांजैक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आने की सूचना अंग्रेजी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं में भी मिलती है। अच्छी साउंड क्वालिटी की वजह से भीड़-भाड़ और शोर के बीच भी पेमेंट की सूचना कारोबार मालिकों को आसानी से मिलती है। इन सारी खबरियों की वजह से यह बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है।

फोनपे के ऑफलाइन बिज़नेस हेड विवेक लोहचेब ने इसे बड़ी उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा, 'डिजिटल पेमेंट भारत में अब लोकप्रिय विकल्प बन चुका है और लोग इसका खूब पैमेंट सुविधा ने नकद लेन-देन की मुश्किलों को काफ़ी हद तक कम किया है।

फोनपे का स्मार्टस्पीकर हमारे मर्चेंट पार्टनर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। खास तौर पर विस्तृत बाज़ार में यह आधुनिक पेमेंट सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही, इसने बड़ी संख्या में कारोबार मालिकों से लोकप्रिय हो रही है और लोग बड़े पैमाने पर इसे अपना भी ज़ड़ने के लिए एक और बड़ा मंच भी तैयार किया है। 3 महीने से भी कम समय में 10 लाख से अधिक डिवाइस का इस्तेमाल बताता है कि यह बार्कइ में कितनी बड़ी उपलब्धि है। रिटेल कारोबार मालिकों के बीच फोनपे की यह उपयोगी सुविधा बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है और लोग बड़े पैमाने पर इसे अपना भी रहे हैं।'

